बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गिरफ्त में पीने का पानी

डॉ. महेश परिमल

पानी से कमाई! भला यह कैसे संभव है? हां पानी तो ऐसी आवश्यक चीज़ है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस समय पानी को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे यह भविष्य में मोटी कमाई का साधन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए बाकायदा साज़िश रची जा रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जाल बिछाया जा रहा है। कुछ देश उनके चंगुल में फंसकर कराह रहे हैं, कुछ छटपटा रहे हैं, तो कुछ उनके चंगुल में जाने के लिए तैयार है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना जाल कुछ इस तरह से फैलाती हैं कि सरकारों को पता ही नहीं चलता।

प्रकृति ने मानव को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया है। पानी को बेचकर कमाई करने का विचार इंसान के भीतर कब-कैसे आया, यह एक शोध का विषय है। देश भर में फैले नदी, तालाब, जलाशय, कुएं, बावड़ियां आदि पानी के वे स्रोत हैं, जिनसे पानी प्राप्त करने के लिए इंसान को कभी उसका मोल नहीं चुकाना पड़ा। पानी के ये स्रोत सभी के लिए उपलब्ध हैं, इसमें कभी भी गरीब-अमीर का भेदभाव नहीं रखा गया।

पानी पर पहले-पहल कब टैक्स लगा, यह किसी को याद नहीं। हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम से देश में बावड़ियां, कुएं, जलाशय, तालाब आदि बनवाए। उन्हीं के इस पराक्रम के कारण आज हमें पानी मिल रहा है। पहले पानी पिलाना पुण्य कार्य हुआ करता था, आज यह धंधा बन गया है।

इस समय गुजरात में पानी के कुएं को सरकारी संपत्ति मानने के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में गुजरात सरकार ने एक विधेयक लाकर यह बताने की कोशिश की है कि राज्य में जितने भी कुएं, बावड़ियां, जलाशय, तालाब आदि हैं, वे अब निजी संपत्ति न होकर सरकारी संपत्ति हैं। यह एक साज़िश है, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, जो दबे पांव हमारे देश में अपना प्रभुत्व फैलाने के लिए आ रही हैं। इन कंपनियों की योजना है कि सरकारों से उनका यह अधिकार छीनकर उन सभी कुओं, बावड़ियों, जलाशयों, तालाबों पर अपना अधिकार जमा लिया जाए। कंपनियों की यह चाल सफल हो जाती है, तो हमारे सभी जल स्रोतों पर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। फिर हमें पीने के पानी के लिए कंपनियों का मुंह ताकना होगा।

हमारे देश में मिनरल वॉटर के उत्पादकों ने पहले-पहल पानी बेचने और उससे कमाई करने की शुरुआत की। मिनरल वॉटर आज भी केवल उच्च वर्ग द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। जिस देश के 90 प्रतिशत लोगों के पास दो टाइम भोजन की समस्या हो, वहां मिनरल वॉटर का इस्तेमाल करना एक सपने की तरह है। इस कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नज़र अब महानगरों के नलों पर है। अभी तक नलों से पेयजल की आपूर्ति नगर निकायों द्वारा की जाती है। इसके लिए नागरिकों से अभी जो कीमत वसूली जाती है, वह काफी कम है। बहुत ही जल्द पेयजल आपूर्ति का यह काम निजी संस्थाओं को दे दिया जाएगा। अभी तो यही कहा जा रहा है कि पेयजल आपूर्ति का काम निजी संस्थाओं को दिया जाएगा, पर इन निजी संस्थाओं के पीछे वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो अपनी चाल इस तरह से चल रही हैं।

इसके बाद सरकार जिन कुंओं, बावड़ियों, तालाबों, सरोवरों, जलाशयों पर अपना अधिकार बता रही है, उसे भी विदेशी कंपनियों को दे दिया जाएगा। यानी कहने को ये हमारे कुएं, हमारी बावड़ी, हमारे तालाब, हमारे जलाशय, हमारे सरोवर होंगे, किंतु इनके पानी पर अधिकार विदेशी कंपनियों का होगा। ये कंपनियां यहीं से पानी लेंगी और उसे मिनरल वॉटर बताकर हमें ही बेचेंगी।

हाल ही में जिन देशों ने अपनी पेयजल व्यवस्था का काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपा है, उनके हाल बहुत ही बुरे हैं। दक्षिण अमरीका के बोलीविया के कोचाबंबा शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था 1999 में अमरीका की कंपनी बेकटेल को सौंपी गई। शहर के सभी तालाबों का अधिकार इस कंपनी को दे दिया गया। इस निजीकरण का सबसे पहला झटका जल दर में दुगनी वृद्धि से लगा। नागरिक अभी संभले भी नहीं थे कि जल दर तिगुनी कर दी गई।

कुछ रसूखदारों ने अपने क्षेत्र में बोरिंग कर पानी की समस्या का हल करना चाहा। पर कुछ दिनों बाद ही कंपनी के अधिकारी वहां पहुंच गए और बोरिंग में मीटर लगाकर टैक्स वसूलने लगे। आरोप यही लगाया गया कि आप भूगर्भ का पानी हमारी अनुमति के बिना इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते ही देखते इस कंपनी ने पानी का दाम इतना अधिक बढ़ा दिया कि एक व्यक्ति के वेतन का 25 प्रतिशत हिस्सा केवल पानी के लिए ही खर्च होने लगा। जो पानी का बिल नहीं दे पाते, उन्हें नल कनेक्शन काट देने की धमकी दी जाती है।

इस तरह की धमकियों से परेशान होकर नागरिक सड़क पर उतरने लगे। कंपनी की मनमानी का विरोध बढ़ने लगा। सरकार नागरिकों का पक्ष लेने की बजाय जाकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के पाले में बैठ गई। आंदोलनकारियों को जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, नागरिकों के आंदोलन पर अंकुश रखने के लिए सेना भी बुला ली गई। सेना के हस्तक्षेप से एक आंदोलनकारी युवक की मौत हो गई। तब सरकार चेती; फिर वही हुआ, जो प्रजा चाहती थी। सरकार ने कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए। जनता ने राहत की सांस ली।

इसके बाद कंपनी ने सरकार पर मुकदमा ठोंक दिया। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी की मानें, तो विश्व में पीने के पानी का बाज़ार करीब एक हज़ार अरब अमरीकी डॉलर का है। यही बहुराष्ट्रीय कंपनी अब भारत पर विश्व बैंक के माध्यम से दबाव बना रही है कि यहां भी पानी का निजीकरण कर दिया जाए। अब संकेत है कि सरकार इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आ गई है। एक सूचना के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश पर देश की 30 नगर पालिकाओं ने पेयजल आपूर्ति के निजीकरण का फैसला कर लिया है। कई निगमों ने इस दिशा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है।

हमारे देश में पानी का 'बाज़ार' अरबों रुपए का है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नज़र अब हमारे देश की तरफ है। बोलीविया में बदनाम हुई कंपनी से वहां की सरकार ने सबक ले लिया, पर हमारी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। इसलिए बेकटेल कंपनी जिन दो कंपनियों का सहयोग कर रही है, वे भारत में सक्रिय हैं।

केवल बेकटेल ही नहीं, बल्कि इसमें गरीब किसानों को लखपति बनाने की सपने दिखाने वाली मोन्सेंटो कंपनी और फ्रांस की जल दैत्य मानी जाने वाली विवेंडी और सुएज़-लियोनेज़ भी शामिल हैं। बेकटेल जिनका सहयोग कर रही है, उन कंपनियों ने अभी तमिलनाडु के तिरुपुर शहर की जलापूर्ति करने के लिए एक हज़ार करोड़ का ठेका प्राप्त किया है। जमशेदपुर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था फ्रेंच कंपनी विवेंडी को सौंपने पर विचार चल रहा है। बैंगलोर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था फ्रेंच कंपनी विवेंडी और नार्थम्ब्रियन कंपनी को सौंपने की सुगबुगाहट है। मुंबई, सूरत, और अहमदाबाद शहर की जल वितरण प्रणाली भी विदेशी कंपनियों को सौंपने पर विचार चल रहा है।

वह दिन दूर नहीं जब हमें पानी की भारी कीमत चुकानी

होगी। हमारे देश के सभी नदी, तालाब, जलाशय, सरोवर आदि के पानी पर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। तब गरीबों के लिए पीने का पानी मिलना अंसभव नहीं, तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। इसका हल यही होगा कि बोलीविया की तरह यहां भी आंदोलन शुरू किया जाए। वहां की सरकार एक मौत से जाग गई थी, पर हमारी सरकार कितनी मौतों पर जागेगी, कहा नहीं जा सकता। ***(स्रोत फीचर्स)***